जैव ईंधन से कम होगा प्रदूषण

उदयपुर. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा वृक्षमूल तैलीय पौधों की उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण गुरुवार को संपन्न हुआ। इसमें जिले के 40 कृषि अधिकारियों एवं 10 प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिया। प्रसार शिक्षा डॉ. जीएस तिवारी ने बताया कि देश में करीब 85 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है, जिस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वृक्षपोषित तिलहनी फसलों के बीजों से प्राप्त तेल में कुछ



तत्व मिलाने पर ईंधन तैयार प्रसार हो ताकि भविष्य में जब विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो जाए तब इससे कार्य चलाया जा सके। बायोफ्यूल प्राधिकरण के विशेषाधिकारी आरके शर्मा ने कहा कि बायोफ्यूल भविष्य का इँधन से प्रदूषण के साथ-साथ इँधन है। पौधों पर आधारित जैव ईँधन जैसे रतनजोत, करंगज, महुआ, नीम को बंजर भूमि पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी अधिकतम खेती की जानी चाहिए, जिसे देश में खाड़ी देशों पर पेट्रोलियम के लिये निर्भरता कम कम होता है, अतः प्रयास है हो जाए। साथ ही बायोम्यूल को मनरेगा एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के साथ कि जैविक इँधन का अधिक जोड़ने का भी आव्हान किया।

अभी पेट्रोलियम आयात पर अरबों स्वर्च

हैं जैव ईंधन : जीएस तिवारी

सिटी रिपोर्टर . उदयपुर

प्रसार शिक्षा निदेशक जीएस तिवारी ने बताया कि देश में करीब 85 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयातित होता है। राजस्थान में प्राकृतिक वृक्ष पोषित तिलहनी फसलों के बीजों से मिलने वाले तेल में कुछ तत्व मिलाने पर ईंधन तैयार हो जाता है।

तिवारी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को जिले के 40 कृषि अधिकारियों और 10 प्रगतिशील किसानों के दो दिवसीय वृक्ष मूल तेलीय पौध उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के समापन सत्र को संबोधित कर रहे प्राप्त ईंधन से प्रदूषण के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम प्रसार हो ताकि भविष्य में जब विश्व है उसमें से 45 लाख हेक्ट्रेयर भूमि

सके। समापन समारोह में किष विभाग के गोपाल शर्मा और डीपी सिंह मौजूद रहे। संचालन लितका व्यास ने किया।

प्रदेश में 103 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि

बायोपयूल प्राधिकरण, जयपुर के आरके शर्मा ने बायोपयूल ही भविष्य का ईंधन है। पौधों पर आधारित जैव ईंधन जैसे रतनजोत, करंगज, महुआ, नीम को बंजर भूमि पर अधिकतम खेती की जानी चाहिए, जिससे देश में खाड़ी देशों पर पेट्रोलियम के लिए विर्भरता कम हो जाए। साथ ही बायोपयूल को मनरेगा और राजस्थान थे। उन्होंने बताया कि इस तरह से ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के साथ जोड़ने का भी आह्वान किया। जैव ईंधन प्रभारी पीसी चपलोत ने कहा कि होता है। जैविक ईंधन का अधिक प्रदेश में 103 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो पर करंज, रतनजोत, महुआ की खेती जाए तब इससे काम चलाया जा आसानी से कर सकते हैं।